

प्रेषक,

अनूप वधावन

सचिव

उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में

निदेशक

पंचायतीराज

उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग: देहरादून : दिनांक 27 मई 2008

विषय:- पंचायतीराज निदेशालय भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 86/पं-2/लेखा/नि.भ./2007-08 दिनांक 21-4-2008 एवं शासनादेश संख्या- 492/XII/06/82(01)-टी0सी0-1 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायतीराज निदेशालय भवन निर्माण हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा गठित कुल आंगणन रु0 152.00 लाख (रु0 एक करोड़ बावन लाख मात्र ) की धनराशि के सापेक्ष टी0ए0सी0 से परीक्षणोंपरान्त पायी गयी औचित्यपूर्ण धनराशि रुपये 129.00 लाख की प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन तथा इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2006-07 में स्वीकृत रुपये 81.52 लाख (रु0 इक्कासी लाख बावन हजार मात्र)के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2008-09 में रुपये 47.48 लाख (रु0 सैंतालीस लाख अड़तालीस हजार मात्र)की धनराशि अवमुक्त करते हुये निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को तथा जो दरे शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, कि स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाए।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भाँति निरीक्षण कर उच्च अधिकारियों द्वारा एवं भूगर्ववेत्ता के साथ आवश्यक करा लें । निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुसार कार्य कराया जाये ।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है व्यय उन्हीं मदों पर किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों पर कदापि व्यय न की जाय ।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

(9) जी0पी0डब्लू फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जाएगा।

- (10) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV -219(2006) दिनांक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- (11) कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी का होगा।
- (12) उक्त स्वीकृत धनराशि शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों / नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाये तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाय। धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायें।
- (13) उक्त धनराशि का व्यय 31.03.2009 तक पूर्णरूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (14) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-19 के अन्तर्गत आयोजनागत मद में पूंजी लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य-01 कार्यालय भवन-001-निर्देशन तथा प्रशासन -04 पंचायतीराज निदेशालय भवन निर्माण -24-वृहत निर्माण कार्य के नामें झाला जायेगा।
- (15) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 54(पी) /XXVII-4/2008 दिनांक 14 / 5/2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,  
/  
(अनूप वधावन)  
सचिव।

संख्या 370/XII/08/82(01)/2004 टी0सी0-1तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. जिलाधिकारी देहरादून/मुख्य विकास अधिकारी देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उत्तरांचल देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा गढ़वाल परिमण्डल पौड़ी/अधिशारी अभियन्ता, ग्रा0अ0से0 प्रखण्ड देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय देहरादून।
10. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के आवलोकनार्थ
11. वित्त अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन।
12. नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. वित्त बजट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से  
/ (एम0सी0उप्रेती)  
अपर सचिव।